बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

ल.अं./51/एसएलबीसी/सितंबर 2025/ 664 22.12.2025

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0) के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय,

विषय : **राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ.प्र.) की सितंबर 2025 त्रैमासांत की बैठक दिनांक 10.12.2025 का कार्यवृत्त**

कृपया दिनांक **10.12.2025** को सम्पन्न राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ.प्र.) की सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही की समीक्षा बैठक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त एवं कार्यवाही बिन्दु आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय,

शैलेन्द्र कुमार सिंह

(शैलेंद्र कुमार सिंह)
महाप्रबंधक एवं संयोजक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0प्र0)

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.), अंचल कार्यालय, लखनऊ अंचल, "बड़ौदा हाउस", वी-23, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010
State Level Bankers' Committee (U.P.), Zonal Office, Lucknow Zone, "Baroda House", V-23, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
फोन / Phone : 0522-6677607 (GM), 6677609 (Sectt.), 6677722 (DGM), 6677730 (CM), 6677721, 6677725
ई-मेल / E-mail : slbc.up@bankofbaroda.com, वेबसाइट / Website : www.slbcup.com

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की सितंबर 2025 तिमाही की बैठक दिनांक 10.12.2025 का कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) की सितंबर 2025 त्रैमासिक समीक्षा बैठक दिनांक 10.12.2025 को **"महाराजा सयाजीराव गायकवाड सभागार", बड़ौदा हाउस, गोमती नगर, लखनऊ** में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्री लाल सिंह, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी।

बैठक में डॉ सारिका मोहन, महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ.प्र. शासन; श्री पंकज कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ; श्री मासूम अली सरवर, आई.ए.एस., सचिव, नियोजन, उ.प्र. शासन; श्री समीर, आई.ए.एस., विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन; श्री पंकज कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, लखनऊ; श्री पवन कुमार, पुलिस उपमहानिरीक्षक, साइबर क्राइम, लखनऊ; श्री जय कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक, सिडबी, लखनऊ; श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, एस.एल.बी.सी. (उ.प्र.) सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारीगणों द्वारा सहभागिता की गई। बैठक में भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 24.09.2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :

जून 2025 त्रैमास की बैठक दिनांक 24.09.2025 के कार्यबिन्दु एवं कार्यवृत्त सभी सदस्यों को एस.एल.बी.सी. के पत्रांक ल.अं./51/एस.एल.बी.सी./जून 2025/484 दिनांक 15.10.2025 के माध्यम से प्रेषित किये गये थे, जिसकी पुष्टि समिति द्वारा की गयी।

बैठक के प्रारम्भ में **श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.)** ने सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश में गठित कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों से सभा को निम्नवत अवगत कराया :

- CKYCRR की महत्ता, कार्यप्रणाली, इससे संबंधित best practices, common errors, और regulatory expectations के बारे मे जागरूक करने के उद्देश्य से दिनांक 31.10.2025 को जनपद लखनऊ में CKYCRR जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमे CERSAI, FIU- India, RBI तथा बैंको के उच्चाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
- सतर्कता जागरूकता अभियान (18.08.2025 से 17.11.2025) के दौरान Vigilance Commissioner, CVC की अध्यक्षता मे जनपद लखनऊ मे दिनांक 11.11.2025 को एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमे प्रदेश मे भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो एवं बैंको के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गई।
- दिनांक 28.11.2025 को जनपद लखनऊ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा LDO/DDM/LDM कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमे प्रदेश में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए बीसी सखी मॉडल, डीसीसी/ डीएलआरसी बैठके तथा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दो पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान अधिकांश LDM द्वारा यह महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया कि कई क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों/विभागों की अनुपस्थिति के कारण BLBC की बैठकें अपने उद्देश्य के अनुरूप प्रभावी नहीं हो पा रही हैं। सभी जिलाधिकारियों, बीडीओ, एवं विभागीय अधिकारियों को BLBC एवं अन्य बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के साथ साथ सभी शाखाओं को BLBC एवं अन्य महत्वपूर्ण बैठकों में अनिवार्य रूप से पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित होने निर्देशित किए जाने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ.प्र. ZONAL OFFICE (LUCKNOW ZONE) लखनऊ

- प्रदेश में साइबर धोखाधड़ी में शामिल धनराशि को अधिक से अधिक संख्या में रोकने हेतु पृथक CFMC लखनऊ में स्थापित किया जा चुका है। प्रथम चरण के अंतर्गत अभी तक इस कॉल सेन्टर में 11 बैंको के अधिकारियों को नियुक्त किया जा चुका है । द्वितीय चरण/ शेष बचे बैंको से अनुरोध है कि अपने बैंक अधिकारियों की उक्त कॉल सेंटर में शीघ्र प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करें। उन्होने सभी बैंको से अनुरोध किया कि CFMC में कार्यरत बैंक अधिकारियों को उनके कार्य के सुचारु संचालन हेतु सभी बैंक नियमित रूप से आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त संबन्धित बैंक)

- वार्षिक ऋण योजना 2025-26 के अंतर्गत आवंटित लक्ष्यों रू 6.45 लाख करोड़ के सापेक्ष कुल रू 3.15 करोड़ (48.85%) की उपलब्धि दर्ज की गई है। एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के अंतर्गत कुल आवंटित लक्ष्य रू 3.66 करोड़ के सापेक्ष रू 2.03 करोड़ (55.37%) की उपलब्धि दर्ज की गई है। साथ ही कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आवंटित लक्ष्य रू 2.43 करोड़ के सापेक्ष रू 10.03 करोड़ (42.28%) की उपलब्धि दर्ज की गई है।

- प्रदेश का ऋण जमानुपात सितंबर 2025 में 59.56 पहुंच गया है। साथ ही 40% से कम ऋण जमानुपात वाले जनपदों की संख्या भी मार्च 2025 के स्तर 7 से घटकर सितंबर 2025 मे 6 रह गई है।

- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु समस्त बैंकों को 1.50 लाख आवेदनों पर ऋण वितरण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना के अंतर्गत प्राईवेट बैंको द्वारा दर्ज प्रगति संतोषजनक नही होने के कारण उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय द्वारा एस.एल.बी.सी. विभाग को योजना के अंतर्गत लक्ष्यो का पुन: आवंटन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया गया था जिसके क्रम में दिनांक 12.11.2025 को योजनान्तर्गत लक्ष्यो का बैंकवार जनपदवार पुन: आवंटन कर (प्राईवेट बैंको के अतिरिक्त) सभी बैंको को अवगत करा दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र एवं RRBs द्वारा पूर्व में भी सरकार प्रायोजित योजनाओ के अंतर्गत बेहतरीन उपलब्धि दर्ज की जाती रही है। सभी बैंको से अनुरोध है कि संशोधित लक्ष्यो को प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रयास किए जाये।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में **श्री लाल सिंह, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा** ने सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों का अभिवादन करते हुए समिति को निम्न महत्वपूर्ण गतिविधियो से अवगत कराया :

- केंद्र सरकार के **'विकसित भारत 2047'** विजन का लक्ष्य वर्ष 2047 में भारत के 100वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को एक पूर्ण विकसित, आत्मनिर्भर, समृद्ध और वैश्विक नेतृत्वकारी राष्ट्र बनाना है। इसमें तेज़ आर्थिक विकास, आधुनिक बुनियादी ढाँचा, बेहतर शिक्षा-स्वास्थ्य, रोजगार बढ़ाना, तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देना तथा सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराना शामिल है। बैंकिंग सेक्टर देश को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में मुख्य भूमिका निभाएगा। बैंकिंग क्षेत्र वित्तीय समावेशन बढ़ाकर हर नागरिक को बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं से जोड़ने, उद्योगों, स्टार्टअप्स और MSME को ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार और आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगा। साथ ही डिजिटल बैंकिंग, फिनटेक, साइबर सुरक्षा और आधुनिक तकनीक के माध्यम से बैंकिंग को तेज़, सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाएगा।

- भारत सरकार के निर्देशानुसार, वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान 01.07.2025 से 31.10.2025 तक देश में ग्राम पंचायत स्तर और शहरी स्थानीय निकायों पर सफलतापूर्वक संचालित किया गया। हर्ष का विषय है कि इस राष्ट्रव्यापी अभियान में उत्तर प्रदेश ने 7 मे से 5 मापदंडो मे PAN INDIA level पर प्रथम स्थान हासिल किया है जिसके लिए उन्होने प्रदेश सरकार के संबन्धित विभागो, समस्त बैंको, अग्रणी जिला प्रबन्धको एवं SLBC की टीम को बधाई दी। जनसुरक्षा पोर्टल पर दिनांक 31.10.2025 तक प्रदेश की स्थिति निम्नानुसार है :

Total Camps Conducted	PMJDY Opened	PMJJBY Enrolled	PMSBY Enrolled	APY Subscribed	No. of Re-KYC done	No. of claims Disbursed	No. of Nominations done	Total
Rank 1st	Rank 1st	Rank 1st	Rank 1st	Rank 1st	Rank 9th	Rank 1st	Rank 4th	Rank 1st
57699	2224816	1714081	4335130	690607	2796826	19527	1240745	13021732

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ०प्र० (LUCKNOW ZONE)

- संतृप्तीकरण अभियान के दौरान re-KYC एक महत्वपूर्ण मानक रहा है, जो वित्तीय समावेशन और खातों की सक्रियता सुनिश्चित करता है। प्रदेश में बड़ी संख्या में re-KYC हेतु खाते लंबित है जिसके लिए बैंकों को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। re-KYC अभियान को सफल बनाने हेतु बैंको से ग्राहक जागरूकता, दस्तावेज़ प्रक्रिया सरलीकरण, डिजिटल साधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए ग्रामीण एवं दूरदराज़ क्षेत्रों तक पहुंच बनाने पर विशेष ध्यान देने हेतु आह्वाहन किया।

- माननीय वित्तमंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 04.10.2025 Unclaimed Deposit हेतु "आपकी पूंजी आपका अधिकार" अभियान का शुभारंभ चरणबद्ध रूप से किया गया है। हमारे प्रदेश में सभी प्रमुख बैंकों के पास लगभग 3.13 करोड़ खातों में ₹ 9,128 करोड़ की राशि Unclaimed है। अद्यतन स्थिति के अनुसार, प्रदेश में कुल 7 चरणों में 50 जनपदों में शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। उन्होने बैंको से आह्वाहन किया कि इस अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार करे ताकि अधिक से अधिक Unclaimed Deposit को निर्धारित समयावधि में settle किया जा सके।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- वित्तीय वर्ष 2025-26 की सितंबर तिमाही के अंत में प्रदेश का कुल बैंकिंग व्यवसाय रु 31.76 लाख करोड़ पहुंच गया है।
- बैंकों ने कुल जमा एवं अग्रिम मे क्रमश: 8.40% एवं 10.53% की YoY Growth दर्ज की है।
- ऋण जमानुपात सितंबर 2025 में 59.56% के स्तर पर पहुंच गया है ।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कृषि एवं एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत ऋण में क्रमश: 14.13%, 6.06% एवं 22.25% की YoY Growth दर्ज की है।
- सरकारी योजनाओं यथा CM YUVA, ODOP, PM SVANidhi, PM SURYA Ghar, PM Vishwakarma, DAY NULM, R-SETI Credit Linkage, SHG Credit Linkage एवं CGTMSE के अंतर्गत और सुधार किए जाने हेतु सभी बैंकों, विशेषकर निजी बैंकों एवं स्माल फ़ाइनेंस बैंकों से अनुरोध किया।

अपने सम्बोधन के अंत में उन्होने सभा में उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए सार्थक चर्चा हेतु शुभकामनाएँ दी।

श्री पंकज कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए अपने संबोधन में निम्न बिन्दुओं से अवगत कराया :

- ऋण जमानुपात में तिमाही दर तिमाही बढ़ोत्तरी हो रही है। सितंबर 2025 में प्रदेश का ऋण जमानुपात 59.56 % के स्तर पर पहुंच गया है। जमा की अपेक्षा अग्रिम में अधिक बढ़ोत्तरी होने से निश्चय ही प्रदेश के ऋण जमानुपात में भी बढ़ोत्तरी होगी। बैंको से आह्वाहन किया कि प्रत्येक जनपद के अग्रिम में औसतन 10% की वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है जिससे ऋण जमानुपात में भी लगभग 2-3% की वृद्धि दर्ज हो सके ।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

- RBI, BSR Return के अनुसार प्रदेश का Incremental CD Ratio में YoY सुधार आया है यह जून 2024 से जून 2025 मे 56.10% तथा सितंबर 2024 से सितंबर 2025 मे 69.10% के स्तर पर रहा है। प्रदेश में अग्रिम के क्षेत्र में पर्याप्त संभावनाएं व्याप्त है। समस्त सरकार प्रायोजित योजनाओ के अंतर्गत प्राप्त होने वाले एवं लंबित आवेदन पत्रों में ऋण वितरण की कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है जिससे प्रदेश के ऋण जमानुपात और अधिक सुधार हो सके।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

- भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए संतृप्तीकरण अभियान के दौरान प्रदेश द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन किया गया। प्रदेश द्वारा पैन इंडिया सर्वाधिक- 57695 ग्राम पंचायतों मे कैंपो का आयोजन किया। ऐसे प्रदेश जिनमे re-KYC हेतु due खातो की संख्या

1 करोड़ से अधिक रही, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार एवं पश्चिम बंगाल है जिसमे से उत्तर प्रदेश मे कुल 4.63 करोड़ खाते जून 2026 तक re- KYC हेतु due है। अद्यतन स्थिति के अनुसार अभी तक कुल 37%- 38% खातो मे re- KYC किया जा चुका है। उन्होने बैंको से अनुरोध किया कि re-KYC हेतु due खातो के लक्ष्यो को हासिल करने के लिए रणनीति बनाते हुए आवश्यक प्रयास करें।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

❖ वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा Unclaimed Deposit को settle करने हेतु शुरू किए गए "मेरी पूंजी मेरा अधिकार" अभियान के अंतर्गत हमारे प्रदेश मे सभी प्रमुख बैंकों के पास लगभग ₹ 9,128 करोड़ की राशि Unclaimed है। अभी तक की प्रगति के अनुसार प्रदेश में 1% खातो को ही settle किया गया है। बैंको को ग्राहको को जागरूक करने एवं अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए अधिक से अधिक धनराशि settle करने हेतु निर्देशित किया।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

❖ वार्षिक ऋण योजना 2025-26 के अंतर्गत सितंबर 2025 मे बैंको द्वारा 48.85% की उपलब्धि दर्ज की है। एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत बेहतरीन उपलब्धि दर्ज की गई है। कृषि प्रधान प्रदेश होने के बावजूद कृषि क्षेत्र मे उपलब्धि संतोषजनक नही रही है। प्रदेश में दीर्घकालिक टिकाऊ कृषि हेतु कृषि ऋण पर फोकस प्रदान करने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए बैंको से पूंजीगत निवेश ऋण को बढ़ाने हेतु आग्रह किया।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

❖ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म -Unified Lending Interface (ULI) पर राजस्व विभाग, उ प्र के साथ समन्वय करते हुए भूमि एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण हो जाएगी जिससे कृषको को रू 2 लाख तक का कृषि ऋण बिना भूमि बंधक के निर्बाध रूप से प्राप्त हो सकेगा। साथ ही CM Yuva yojana को भी ULI से integrate किए जाने की प्रक्रिया जारी है ताकि योजना के लाभार्थियो को आसानी से कम समय मे ऋण ऋण प्राप्त हो सके।

❖ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में Financial Literacy Week का आयोजन किया जाता है। आगामी फरवरी माह में आयोजित होने वाले FL Week में KYC/re-KYC के मुख्य बिन्दु रहेगा।

❖ गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक ने 01.12.2025 को सचिव, वित्तीय समावेशन विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति 2025-30 से अवगत कराया है। इसका उद्देश्य आजीविका, कौशल विकास और सहायक पारिस्थितिकी तंत्र को वित्तीय समावेशन के साथ एकीकृत करना है। साथ ही महिलाओं के नेतृत्व वाले वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण अपनाना और परिवारों की वित्तीय मजबूती में सुधार के लिए, विशेष रूप से वंचित और कमजोर वर्गों के लिए विभेदित रणनीतियाँ तैयार करना भी है।

❖ आगामी वित्तीय वर्ष (2026-27) हेतु वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत सेक्टरवार आवंटित होने वाले लक्ष्यो की तैयारी शुरू हो चुकी है। उन्होने समस्त संबन्धित विभाग से अनुरोध किया कि आगामी वर्ष हेतु लक्ष्यो को तैयार करने मे पूर्ण सावधानी बरती जाये, लक्ष्य आकांक्षात्मक, जनपदो में विभिन्न सेक्टरों मे व्याप्त संभावनाओ के अनुसार होने के साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष मे दर्ज प्रगति के अनुरूप हो।

डॉ. सारिका मोहन, आई.ए.एस., महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं बाह्य सहायतित विभाग, उ. प्र. शासन ने अपने सम्बोधन में सभा को निम्न मुख्य बिन्दुओ से अवगत कराया :

❖ सर्वप्रथम उन्होने बताया कि एसएलबीसी फोरम एक महत्वपूर्ण फोरम होने के साथ साथ एक ऐसा मंच है जहां जनपद स्तर एवं प्रदेश स्तर दोनो ओर से संवाद होता है। जनपद स्तर पर होने वाली बैठको मे महसूस की जा रही समस्याओं यथा

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ.प्र. ZONAL OFFICE (LUCKNOW ZONE) आंचलिक कार्यालय

जनपद स्तरीय अधिकारियों इत्यादि की बैठको उपस्थिति इत्यादि के बारे में अग्रणी जिला प्रबन्धको को निर्देशित किया कि बैठक के एजेंडा बिन्दुओ की महत्ता एवं मुद्दो को बताते हुए उनकी सुविधानुसार समय लेकर ही बैठक की तिथि का निर्धारण करें।

❖ विकसित यू पी के लिए जनपदो में दौरे के दौरान सामने आया कि स्वयं सहायता समूह की सदस्यो के खाते खोलने, वित्तीय लेनदेन की ट्रेनिंग प्रदान करने एवं क्रेडिट लिंकेज प्रदान करने के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया गया है जिसके लिए सभी बैंक को बधाई दी।

❖ विकसित यू पी और $ 1 trillion अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में बैंक ऋण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। जहां एक ओर कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के अग्रिम में बढ़ोत्तरी हुई है वही दूसरी ओर कुछ बैंकों यह प्रगति बहुत धीमी है। समस्त बैंको को अग्रिम बढ़ाने हेतु निर्देशित किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

❖ प्रदेश के ऋण जमानुपात में जून 2025 के सापेक्ष सितंबर 2025 मे बढ़ोत्तरी हुई है। उन्होने जनपदो को ऋण जमानुपातवार वितरित करते हुए 3-4 श्रेणियों में बांटकर प्रगति समीक्षा किए जाने, साथ ही ऐसे जनपद जिनमे संभावना अनुरूप अग्रिम में वृद्धि दर्ज नही हो रही है, मे एक विशेष कार्ययोजना बनाकर प्रयास किए जाने हेतु अनुरोध किया ताकि प्रदेश के ऋण जमानुपात को 65% से 70% तक पहुंचाया जा सके।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

❖ उन्होने बताया कि ODOP 2.0 प्रस्तावित है जिसमे export, larger market & sustainable employment पर फोकस रहेगा। बैंको द्वारा पूर्व मे भी योजनान्तर्गत बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है। बैंको से आह्वाहन किया कि पूर्व की भांति इस बार भी अधिक से अधिक लोगो को योजना का लाभ पहुंचा जाये।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

❖ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमे रबी 2025-26 मौसम के दौरान अधिक से अधिक के सी सी धारको को फसल बीमा योजना के अंतर्गत आच्छादित किए जाने हेतु निर्देशित किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

❖ संस्थागत विभाग की ओर से बैंको और राजस्व विभाग को बैंक ड्यूस एवं आर सी खातो की वसूली हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किए जाने हेतु आश्वासन देते हुए राजस्व विभाग से थोड़ा ज्यादा सक्रिय होकर आरसी खातो की वसूली हेतु रणनीति बनाते हुए प्रयास किए जाने हेतु निर्देशित किया।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, उ प्र)

सम्बोधन के अंत में उन्होने बैंको द्वारा प्रदेश मे किए जा रहे बेहतरीन कार्यो के लिए बधाई देते हुए इसे बनाए रखने के साथ साथ अन्य क्षेत्रो में भी बेहतरीन प्रदर्शन करने हेतु शुभकामनाएं दी।

श्री मासूम अली सरवर, आई.ए.एस., सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन ने अपने सम्बोधन में निम्नवत अवगत कराया :

❖ प्रदेश के 6 जनपदो का ऋण जमानुपात 40% से कम है। ऐसे जनपद जिनका ऋण जमानुपात 40% से कम है, में विशेष प्रयास करते हुए ऋण जमानुपात बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये।

(कार्यवाही: संबन्धित अग्रणी बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक)

❖ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अग्रिम बढ़ाए जाने हेतु बैंको से आह्वाहन किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA ZONAL OFF. (LUCKNOW ZONE)

❖ प्रदेश में जून 2025 से सितंबर 2025 मे बैंक शाखाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है जबकि प्रदेश मे ग्रामीण क्षेत्रो मे कार्यरत शाखाओ की संख्या में कमी आई है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही: संबन्धित बैंक)

❖ प्रदेश सरकार की एक ग्राम पंचायत एक बी. सी. कार्यक्रम के अंतर्गत 58,000 ग्राम पंचायतों मे बी सी सखियों को ऑनबोर्ड किया जाना था जिसके सापेक्ष अभी तक 39,875 बी सी सखियों को ऑनबोर्ड किया जा चुका है। बी सी सखियों के 58,000 ग्राम पंचायतों में ऑनबोर्ड होने से ब्रिक & मोर्टार शाखाओ की आवश्यकता नहीं होगी।

(कार्यवाही: संबन्धित बैंक)

श्री समीर, आई.ए.एस., विशेष सचिव, वित्त, उ.प्र. शासन ने अपने सम्बोधन के माध्यम से सर्वप्रथम ऐसे जनपद जिनका ऋण जमानुपात 40% से कम है, के ऋण जमानुपात को 40% से बढ़ाए जाने हेतु विस्तृत रूपरेखा/कार्ययोजना, 40%- 50% की श्रेणी में आने वाले जनपदो के अग्रिम को बढ़ाने हेतु आवंटित लक्ष्यो के सापेक्ष अद्यतन स्थिति इत्यादि के बारे मे अवगत कराये जाने हेतु अनुरोध किया।

❖ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में विशेषकर कृषि अवसंरचना के अंतर्गत हो रही कम प्रगति पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे बढ़ाए जाने हेतु समस्त बैंको से आह्वाहन किया।

(कार्यवाही: संबन्धित बैंक)

❖ प्रदेश मे कार्यरत बी सी सखियो का बैंक व्यवसाय के प्रति रुचि, कतिपय कारणो यथा मशीन का मुद्दा, कमीशन का मुद्दा इत्यादि से, कम हो रहा है जो ग्रामीण आजीविका मिशन को प्रभावित करेगा। बी सी सखियो से संबन्धित मुद्दो का निवारण किए जाने हेतु बैंको एवं संबन्धित विभाग से अनुरोध किया।

(कार्यवाही: संबन्धित बैंक एवं UPSRLM Deptt.)

❖ सामाजिक सुरक्षा योजना यथा PMJJBY, PMSBY &APY के अंतर्गत क्लेम निस्तारण की अद्यतन स्थिति एस एल बी सी बैठक की प्रस्तुति मे शामिल किए जाने हेतु अनुरोध किया ।

(कार्यवाही: एस.एल.बी.सी. विभाग)

❖ भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए संतृप्तीकरण अभियान के दौरान प्रदेश को अधिकांश पैरामीटर्स पर प्रथम स्थान प्राप्त होने पर समस्त बैंको को बधाई दी।

❖ गत वर्ष सरफेसी एक्ट के अंतर्गत लंबित आवेदन पत्रो के निस्तारण हेतु मुख्य सचिव, उ प्र शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों एवं SPs हेतु एक विस्तृत SOP जारी की गई थी। बैंको से आहवाहन किया कि ऐसे आवेदन जो विभिन्न न्यायालयों मे लंबित है, की सूची संस्थागत वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

❖ उन्होने बताया कि विभिन्न सरकारी योजनाओ के अंतर्गत मिलने वाले लाभों यथा कृषि, शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत बीज, किताबे, बैग इत्यादि को कैश में न कर CBDC के माध्यम से reimburse कर प्रदान किया जाये।

श्री पंकज कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, लखनऊ ने अपने संबोधन में बैठक में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए सदन को निम्न बिन्दुओं से अवगत कराया:

❖ कृषि क्षेत्र के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्यो एवं वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों में लगभग रू 28,500 करोड़ का अंतर है जिसे कृषि ऋण हेतु अवशोषित (absorb) किए जाने की आवश्यकता है।

- ऋण जमानुपात को बढ़ाने हेतु विस्तृत विश्लेषण में पाया गया कि प्रति शाखा अग्रिम एक बहुत अच्छा मैट्रिक्स है। ऋण जमानुपात वास्तव में विभिन्न संकेतकों के साथ सह-संबंधित (Correlated) है। साथ ही प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऐसे जनपद, जिनका ऋण जमानुपात 40 से अधिक अथवा 40 से कम है, के समूह की धीमी ऋण दर को प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं। सर्वे के अनुसार, प्रदेश के समस्त 75 जनपदो को 4 समूहो मे विभाजित कर ऋण दर को बढ़ाने की मानीटरिंग किए जाने की आवश्यकता है।

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित LDM/DDM कान्फ्रेंस के दौरान आगामी वित्तीय वर्ष हेतु ब्लॉक स्तर पर दिये जाने वाले लक्ष्यो को सावधानी से तैयार किए जाने हेतु अग्रणी जिला प्रबन्धको को निर्देश दिये गए है।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक)

- प्रदेश मे किसान क्रेडिट कार्ड की संख्याओ में हो रही कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि मार्च 2025 से सितंबर 2025 में 75 जनपदों में से 28 जनपदो मे केसीसी की संख्या में गिरावट आई है जबकि 3 जनपदो मे केसीसी की संख्या 50,000 से अधिक है एवं 9 जनपदो मे केसीसी की संख्या 10,000 से अधिक है। ऐसे जनपदो मे एक अलग कार्ययोजना अपनाएं जाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक)

- प्रदेश मे e- NWR के अंतर्गत जनपदवार लक्ष्यो का आवंटन किया जा चुका है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं ऋण प्रदान करने में जनपदों एवं बैंक शाखाओ को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके लिए नाबार्ड द्वारा Capacity Building कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमे बैंक शाखाओ द्वारा प्रतिभाग किया जाने हेतु आह्वाहन किया। इस योजना के अंतर्गत ऋण प्रवाह निश्चय ही कृषि क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्यों को हासिल करने में यथासंभव मदद करेगा।

(कार्यवाही: नाबार्ड, समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक)

- इसी प्रकार, Allied Sector के अंतर्गत भी लक्ष्यो का आवंटन किया जा चुका है तदापि पशु एवं मत्स्य पालन के अंतर्गत केसीसी की संख्या में बढ़ोत्तरी दर्ज नही हो रही है जिसे बढ़ाने हेतु और अधिक फोकस की आवश्यकता है। इसके लिए जनपद स्तर पर DDM, NABARD द्वारा कार्यशालाओ का भी आयोजन किया जा रहा है जिसमे बैंक शाखाओ द्वारा प्रतिभाग किया जाने हेतु आह्वाहन किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- Agriculture Infrastructure Fund Scheme की प्रभावी मानीटरिंग किए जाने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए योजनानतर्गत अधिक से अधिक ऋण प्रदान किए जाने हेतु बैंको से आह्वाहन किया ताकि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत टर्म लोन को बढ़ाया जा सके।

(कार्यवाही:समस्त सदस्य बैंक)

<u>पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति :</u>

- ✓ सर्वप्रथम गत एसएलबीसी की बैठक के दौरान उभरे कार्यवाही बिन्दुओ पर विस्तृत चर्चा की गई एवं शीघ्र निरस्तारण हेतु संबन्धित विभागो से अनुरोध किया गया।

- ✓ बैंकिंग संबंधी महत्वपूर्ण संकेतको यथा जमा, अग्रिम, ऋण जमानुपात, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कृषि एवं एमएसएमई के अंतर्गत अग्रिम इत्यादि से अवगत कराया गया।

- ✓ राजस्व विभाग द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत आर सी पोर्टल पर बैंको द्वारा वसूली धनराशि अद्यतन किया जाना अपेक्षित है जिसके फलस्वरूप प्रदेश मे आर सी खातो की संख्या एवं धनराशि मार्च 2025 के स्तर 10.70 लाख

खाते (रू 20,044 करोड़) से घटकर सितंबर 2025 में 9.24 लाख खाते (रू 17,388 करोड़) पहुंच गई है। बैंको से अनुरोध किया कि ऐसे खाते जिनमे वसूली की जा चुकी है, की स्थिति पोर्टल पर अवश्य अपडेट करें ताकि वास्तविक स्थिति परिलक्षित हो सके।

(कार्यवाही:समस्त सदस्य बैंक)

✓ सरफेसी खातो की संख्या एवं धनराशि मार्च 2025 के स्तर 4,833 खाते (रू 1706 करोड़) से बढ़कर सितंबर 2025 में 5,190 खाते (रू 3107 करोड़) पहुंच गई है। धनराशि मे दर्ज बढ़ोत्तरी विशेषत: पंजाब नेशनल बैंक (रू 1138 करोड़), केनरा बैंक (रू 122 करोड़), एक्सिस बैंक (330 खाते, रू 98 करोड़) एवं आईसीआईएसी बैंक (रू 57 करोड़) के कारण है। अद्यतन स्थिति के अनुसार, राजस्व विभाग द्वारा बनाए जा रहे पोर्टल हेतु समिति द्वारा एक प्रारूप बनाकर प्रेषित किया जा चुका है जो राजस्व विभाग एवं NIC के मध्य आगे की कार्यवाही हेतु लंबित है।

✓ वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5 New Unbanked Villages की सूची प्रेषित की गई जिन्हे बैंको को शाखा खोलने हेतु आवंटित किया जा चुका है। ग्राम किलौहा, महोबा (केनरा बैंक) मे 22.10.2025 को शाखा खोली जा चुकी है। ग्राम रानाहोर, सोनभद्र (इंडियन ओवरसीज बैंक) मे 31.12.2025 तक शाखा खोली जानी है। ग्राम मड़ैया, चित्रकूट (भारतीय स्टेट बैंक), ऊंचाडीह, चित्रकूट (बैंक ऑफ बड़ौदा) तथा अकथौहा, महोबा (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) मे शाखा खोलने हेतु आवश्यक सपोर्ट हेतु एसएलबीसी द्वारा संस्थागत वित्त विभाग से अनुरोध किया गया था। अद्यतन स्थिति के अनुसार संस्थागत वित्त विभाग द्वारा भी जिलाधिकारी महोदाय से आवश्यक सपोर्ट हेतु अनुरोध किया जा चुका है।

(कार्यवाही: संबन्धित बैंक)

✓ **विशेष सचिव, वित्त ने बताया कि** कोपरेटिव बैंक के जमा में 11% की YoY वृद्धि दर्ज हुई है परंतु अग्रिम में 3% की कमी आई है साथ ही स्माल फाइनेंस बैंक मे जमा एवं अग्रिम मे क्रमश: 21% एवं 9% की YoY वृद्धि हुई है जिससे प्रदेश का कुल ऋण जमानुपात प्रभावित हो रहा है।

(कार्यवाही: उ प्र कोपरेटिव बैंक एवं स्माल फाइनेंस बैंक)

✓ मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने उ प्र कोपरेटिव बैंको को निर्देशित किया कि अपनी समस्त DCCBs का जमा एवं अग्रिम का डाटा संकलित कर ही एसएलबीसी को तिमाही आधार पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: उ प्र कोपरेटिव बैंक)

✓ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा FI Indicators - Access & Uses के अंतर्गत ऐसे जनपद Pan इंडिया में bottom 10 percentile मे आते है, की सूची साझा की है जिनमे फोकस करते हुए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही: संबन्धित अग्रणी बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक)

✓ आपकी पूँजी आपका अधिकार अभियान के अंतर्गत settle हो रहे खातो की जनपदवार सूचना एसएलबीसी को भेजने हेतु बैंको से अनुरोध किया ताकि उक्त सूचना अग्रणी जिला प्रबन्धको से साझा कर जनसुरक्षा पोर्टल पर अपलोड कराई जा सके।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

✓ **विशेष सचिव, वित्त** ने बैंको से आह्वाहन किया कि बैंक शाखाओ द्वारा फर्म, व्यापारिक ईकाई इत्यादि का चालू खाता खोलते वक्त केवाईसी के रूप में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अवश्य लिया जाये जो कि प्रदेश में कार्यरत रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ में रजिस्टर रहता है।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

BANK OF BARODA ZONAL OFFICE (LUCKNOW) अंचल कार्यालय

✓ **श्री पवन कुमार, पुलिस उपमहानिरीक्षक, साइबर क्राइम, लखनऊ** ने बताया कि वित्तीय परिपेक्ष्य में वर्तमान में प्रदेश में साइबर फ्राड्स की राशि उत्तर प्रदेश पुलिस के वार्षिक बजट से भी काफी अधिक है। गृह मंत्रालय द्वारा Indian Cyber Crime Coordination Centre के नाम से एक संस्था बनाई गई जिसने नेशनल साइबर हेल्प लाइन नंबर 1930 का निर्माण किया जिस पर कॉल कर साइबर फ्राड्स से पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत रजिस्टर करा सकता है। उन्होने साइबर हेल्प लाइन नंबर 1930 एवं वेबसाइट - www.cybercrime.gov.in की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत से बताया। उन्होने बताया कि 90% साइबर फ्राड्स जिन 18 शीर्ष बैंक से संबन्धित है, मे से 11 बैंको के अधिकारी CFMC सेंटर पर नियुक्त किए जा चुके है जिसमे से 9 बैंको मे से 5 बैंको के पास सिस्टम एक्सेस नही है। उन्होने बैंको से अनुरोध किया कि CFMC सेंटर पर सिर्फ authorized Person ही प्रतिनियुक्त कि जाये ताकि शिकायत प्राप्त होने पर on the spot खातो में रोक लगाकर आगे की कार्यवाही की जा सके। साथ ही ऐसे बैंक जिन्होंने अपने अधिकारी अभी तक सेंटर पर नियुक्त नही किए है, उन्हे नियुक्त करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: संबन्धित बैंक)

उन्होने बताया कि विभाग द्वारा बैंको से Mule Accounts की सूची साझा की जा रही है जिनके माध्यम से साइबर फ्राड्स की धनराशि जा रही है। Mule Accounts में KYC के नियमों का कड़ाई से अनुपालना किए जाने हेतु बैंको से अनुरोध किया। उन्होने यह भी बताया कि दिनांक 01.12.2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है जिसमे पुलिस एजेन्सीज की रिपोर्ट के आधार बैंको द्वारा Debit Freeze लगाए जाने का निर्णय लिये जाने से अवगत कराया गया है।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

✓ गत एसएलबीसी की बैठक दिनांक 24.09.2025 में अध्यक्ष, एस.एल.बी.सी. द्वारा दिये गए निर्देशों के क्रम में प्रदेश में ऋण जमानुपात पर गठित उपसमिति के संयोजक बैंक - यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 40% से कम ऋण जमानुपात वाले 6 जनपदो के ऋण जमानुपात को 40% से ऊपर पहुंचाने हेतु एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। उक्त प्रस्तुति में जनपदो में ऋण जमानुपात बढ़ाने हेतु विश्लेषणात्मक अध्ययन कर जनपद में वर्तमान बैंकिंग आंकड़े, व्यावसायिक एवं कृषि संबंधी गतिविधियां के साथ जनपद में उपलब्ध ऋण संभावनाओं एवं स्थापित होने वाले नई परियोजनाओ के संबंध मे सदन को अवगत कराया ।

✓ RSETIs के बीपीएल दावों की प्रतिपूर्ति हेतु सितंबर 2025 तक रू 100.55 करोड़ की धनराशि प्रदेश मे काफी समय से लंबित है। **यू.पी.एस.आर.एल.एम. के प्रतिनिधि** ने सदन को अवगत कराया कि रू 20 करोड़ की क्लेम राशि विभाग को प्राप्त हो गई तथा रू 63 करोड़ के क्लेम ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजे जा चुके है।

✓ **महाप्रबंधक एवं संयोजक, एसएलबीसी** ने एक बार पुन: यूपीएसआरएलएम प्रतिनिधि से अनुरोध किया कि लंबित क्लेम धनराशि की प्रतिपूर्ति अतिशीघ्र दिनांक 31.12.2025 तक बैंको को देने हेतु कार्यवाही करें ताकि आरसेटी निर्बाध रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर सके।

State Director, RSETI ने यूपीएसआरएलएम विभाग से अनुरोध किया कि बीपीएल क्लेम की धनराशि क्लेम करने एवं बैंको को प्रतिपूर्ति दिये जाने हेतु एक समय सीमा का निर्धारण अवश्य करें ताकि क्लेम अधिक दिनो तक लंबित न रहे।

(कार्यवाही: यू.पी.एस.आर.एल.एम. विभाग)

✓ प्रदेश मे 5 जनपद RSETI- वैकल्पिक भूमि आवंटन हेतु लंबित है। **State Director, RSETI** ने सदन से अनुरोध किया कि संबन्धित बैंक एवं विभाग समन्वय स्थापित कर भूमि आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे। साथ ही उन्होने सभी बैंकों से आरसेटी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियो को दिये जाने वाली ऋण से संबन्धित डाटा को एसएलबीसी एवं स्टेट डाइरेक्टर को उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

✓ **अध्यक्ष, एस.एल.बी.सी. ने** आरसेटी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियो को प्रशिक्षण पूर्ण होते ही अनिवार्यत: जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से ऋण हेतु आवेदन कराना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया ताकि ऐसे अभ्यर्थियो का डाटा तैयार हो सके जो प्रशिक्षण के पश्चात ऋण लेने हेतु इच्छुक है।

(कार्यवाही: समस्त आरसेटी संयोजक बैंक)

✓ **यू.पी.एस.आर.एल.एम. के प्रतिनिधि** द्वारा अवगत कराया गया कि बैंको के सहयोग से स्वयं सहायता समूह - बैंक लिंकेज के अंतर्गत प्रदेश को आवंटित लक्ष्य 2.86 लाख SHGs (रू 4,000 करोड़) के सापेक्ष अभी तक कुल 1.92 लाख SHGs (रू 2,096 करोड़) का ऋण वितरण किया जा चुका है। SHG Bank Linkage का ticket size 1.50 होना चाहिए जो वर्तमान मे 1.08 है जिसे राष्ट्रीय स्तर 1.50 तक पहुंचाने हेतु ऋण वितरण हेतु लंबित समस्त आवेदन पत्रो के शीघ्र निस्तारण किए जाने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

✓ **KVIC के प्रतिनिधि** ने बताया कि PMEGP योजनान्तर्गत प्रदेश को आवंटित लक्ष्यो को प्राप्त (124%) किया जा चुका है। योजनान्तर्गत सब्सिडी जारी करने हेतु वित्त पोषित इकाइयों का 3 वर्षो पश्चात Physical Verification किए जाने का प्रावधान है जिसके लिए बाह्य एजेंसी - Deptt of Post को नामित किया गया है। एजेंसी द्वारा वर्ष 2019-20 एवं 2021-22 का Physical Verification का कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होने वर्ष 2022-23 हेतु लंबित Physical Verification के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान किए जाने हेतु बैंको से अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

✓ **सूडा विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि** ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश को पी. एम. स्वनिधि योजना के अंतर्गत 5 वर्षो हेतु वर्ष 2030 तक 10 लाख स्ट्रीट वेंडर्स (प्रतिवर्ष 2 लाख स्ट्रीट वेंडर्स) को ऋण प्रदान किए जाने का लक्ष्य प्रदान किया गया है। अद्यतन स्थिति के अनुसार प्रदेश में योजनान्तर्गत स्वीकृति एवं वितरण हेतु क्रमश: 1.59 लाख एवं 0.33 लाख आवेदन पत्र लंबित है। समस्त बैंको से अनुरोध किया कि समस्त आवेदन पत्रो का निस्तारण त्वरित गति से करना सुनिश्चित करें ताकि प्रदेश को आवंटित लक्ष्यो को हासिल किया जा सके।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

✓ **एम.एस.एम.ई. विभाग के प्रतिनिधि** ने सर्वप्रथम CM Yuva योजनान्तर्गत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बैंको को बधाई दी। ऐसे बैंक, जिनकी प्रगति प्रदेश स्तर (50%) से कम है, से आवश्यक प्रयास करते हुए आवंटित लक्ष्यो को हासिल करने एवं ऐसे बैंक जिनके द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है, को लक्ष्यो को सरपास किए जाने हेतु अनुरोध किया। योजना के अंतर्गत मार्जिन मनी क्लेम हेतु लंबित 10,630 आवेदन पत्रों में मार्जिन मनी क्लेम किए जाने हेतु बैंको से अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

✓ **PM SVAMITVA योजना** के अंतर्गत बैंको के प्रधान कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों को एसएलबीसी के साथ साझा किए जाने हेतु अनुरोध किया गया साथ ही यदि बैंको द्वारा योजनान्तर्गत ऋण प्रदान किए जा रहे है, तो इसकी सूचना त्रैमासिक आधार पर SLBC India Portal एवं साप्ताहिक आधार पर अग्रणी जिला प्रबन्धक को भेजना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

✓ सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं यथा CM Yuva, PMFME, PM Surya Ghar, PM Vishwakarma, AIF, ODOP, MYSY इत्यादि में अधिक से अधिक ऋण वितरण किए जाने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

अंत में बैठक श्री मिथलेश कुमार, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, वाराणसी अंचल के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

****

State Level Bankers' Committee Meeting for Quarter ended September 2025

Date 10.12.2025

PARTICIPATION SHEET

Sr. No.	Name of the Participant	Designation	Bank/Deptt.	Telephone/ Mobile No.	Email Address	Signature
1.	Shri Lal Singh	Executive Director	Bank of Baroda, Mumbai			
2.	Shri Pankaj Kumar	Regional Director	Reserve Bank of India, Lucknow	9930676708	pankajkumar@ rbi.org.in	[signature]
3.	Dr. Sarika Mohan, IAS,	Director General	DIF, GoUP			
4.	Shri Masoom Ali Sarwar, IAS,	Secretary	Planning Deptt., GoUP	9927604170	masoom.sarwar @ias.nic.in	[signature]
5.	Shri Sameer, IAS	Special Secretary	Finance, GoUP	9415087120	comodiu@gmail.com	[signature]
6.	Shri Pankaj Kumar	Chief General Manager	NABARD, Lucknow	9833552432	lucknow@nabard.org	[signature]
7.	Shri Pawan Kumar	Deputy Inspector General of Police	Cyber Crime	8299091188	Dig-cyber.lu@up.gov.in	[signature] 10.12.25
8.	Shri Shailendra Kumar Singh	GM & Convenor	SLBC (UP)			
9.	Rohan JHA	Addl SP Cyberpolice	Cyber Crime	[illegible]	sp.cyber.lu @ up.gov.in	[signature]
10.	Arvind Missra	S.P, E.O.W. Lucknow	E.O.W.	9454400232	arvind.misra 777@gmail.com	[signature] 10/12/25
11.	Sarveshwar Shukla	Joint comm./ Nodal officer CM YUVA	Industries	9415054007	cmmyuva@gmail.com	[signature]

Sr. No.	Name of the Participant	Designation	Bank/Deptt.	Telephone/ Mobile No.	Email Address	Signature
12.	सुधा देवी गुप्ता	J.M.D.	UPSRLM	7007592938	mdupsrlm9@.com	Sudha
13.	गिरीश कु० राठौर	Sr. Investigator	NCSC, GoI	7734967774	gireeshrathore@gmail.com	[illegible]
14.	Bikram Bharat Raj Singh	Investigator	NCSC, GoI	8299549039	bharatsingh1002@gmail.com	Bharat
15.	Ashutosh Kr. Singh	Asst. Director	KVIC, GOI	9415463417	kvic-lko2011@gmail.com	Singh
16.	Rajeev Tyagi	Dyceo	UPKVIB.	8383085208	ceoupkvib@gmail.com	[illegible]
17.	RK Saxena	State Director Rseti	MORD	7225055262	sdlucknow.saxena@gmail.com	[illegible]
18.	Sonali Das	General Manager	RBI	9836107580	sonalidas@rbi.org.in	SDas
19.	Dr. Nandini Ghose	General Manager	NABARD	9004317048	nandini.ghose@nabard.org	NGhose
20.	Jay kumar Gupta	General Manager	SIDBI	7237058888	jaykgupta@sidbi.in	[illegible]
21.	Yadav S. Thakur	UPGB - Chairman	UPGB	7500262165	ysthakur1962@gmail.com	[illegible]
22.	Mithilesh Kumar	General Manager	BOB	7506564044	mithilesh.kumar@bankofbaroda.com	[illegible]
23.	Kaushalendra Kumar	General Manager, NW3, LKO	SBI	9004961122	GM3.LHOLUC@sbi.co.in	[illegible]
24.	Vibhor Kumar	DM (ABU) LKO	SBI	8349607498	abu.dgmaby.lucknow@sbi.co.in	[illegible]
25.	Mrityunjay	G.M.	PNB	9810509405	Mrityunjay@pnb.co.in	[illegible]
26.	Sudhir K Gupta	CGM	Indian Bank	9909922454	Sudhir.gupta@indianbank.co.in	[illegible]
27.	A. K. Khanna	ZH	Central Bank of India	8303713848	zmluckzo@centralbank	[illegible]
28.	Amrendra Kumar	GM	BOI	9431623272	FGMO.lucknow@bankofindia.bank.in	[illegible]
29.	Rajesh Kumar	GM	UBI	9836800115	Fgm.lucknow@unionbankofindia.bank	[illegible]
30.	H. Raghu Raja	Dy. GM	Canara Bank	9449777001	colucb@canarabank.com	[illegible]
31.	Amit Goyal	Zonal Manager	Bank of Maharashtra	9893003610	zmlucknow@mahabank.co.in	[illegible]
32.	MANOJ KUMA	Zonal Head	IDBI Bank	7622019804	KUMAR.MANOJ@IDBI.co.in	[illegible]
33.	NIKITA PANDEY	DZH (AGM)	UCO Bank	9572944545	uco.zolucknow	[illegible]
34.	SYED ABDUL KHADER AMBALAM	AGM	IOB	9952033540	syedabdulkhadera@iobnet.co.in	[illegible]

Sr. No.	Name of the Participant	Designation	Bank/Deptt.	Telephone/ Mobile No.	Email Address	Signature
35.	Shiv Shankar	Dy Director	DIF UP	9935069749	director.general.difup@...	[signature]
36.	BABLESH KUMAR	ARO	DIF.U.P	9452034580	-do-	[signature]
37.	Brijesh Kumar	SP Crime	Police	8810822028	—	[signature]
38.	Alok Mourya	Assistant Director	DIF	8700261618	—	[signature]
39.	Sanjay	SPO	UP NEDA	9415609032	—	[signature]
40.	S.D. Dubey	Adviser	NEDA	7607262706	shyamdube05@gmail.com	[signature]
41.	Ashutosh Singh	AM	UIDAI	7388750904	am-2.rolko@uidai.net.in	[signature]
42.	J.N. Yadav	DD	Agriculture statistics	7839082106		[signature]
43.	Dr. Kamal Kr. Singh	SMM	SUDA UP	9151999025	nulmup@gmail.com	[signature]
44.	JC Talukdar	Asstt. Director (VI)	SO, KVIC, Lucknow	7641921627	kvr.lko2011@gmail.com	[signature]
45.	MONICA MALHOTRA	DGM	NATIONAL HOUSING BANK	9810515354	monica.malhotra@nhb.org.in	Monica
46.	A N Singh	ZM, Punjab & Sind Bank	PSB	9917246207	awdhesh.singh@psb.banking	[signature]
47.	K.B. LAL	DGM, UPSGVB	UPSGVB, Lko	9415093570	upsgvb@yahoo.in	[signature]
48.	MAYURI SAXENA	Chief MANAGER, APB	APB	9935099460	MAYURI.SAXENA@AIRTELBANK.COM	[signature]
49.	ASHISH NIGAM	Chief Manager, APBL	APBL	9935099063	ashish.nigam@airtelbank.com	Ashish
50.	PATANJAL RAI	Sr. Manager	IPPB	8888852316	uttarpradesh.circle@ippbonline.in	[signature]
51.	Sushil Mishra	AGM	IDBI	7999857638	mishra.sushil@idbi.co.in	[signature]
52.	Haider	Sr. Manager	Fino PB	8795022290	S.haider@finobank.in	Haider
53.	Amit Saxena	Sr. Manager	"	6391486257	Amit.Saxena@finobank.in	Amit
54.	Yatendra Singh	Deputy Manager	AU Small Finance Bank	7068008404	yatendra.4singh@aubank.in	Yatendra
55.	Aneshad Singh	AM	Jana Small Finance Bank	9235499300	singh.aneshad2016@gmail.com	[signature]
56.	NIRMAL KUMAR	AREA HEAD, Lucknow	UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LTD	9878623454	NIRMAL.KUMAR366@UJJIVAN.COM	Nirmal Kumar
57.	Abhishek kumar	Chief Manager (AVP)	Federal Bank	7488138107	lkw@federalbank.co.in	[signature]
58.	Khyati Srivastava	AVP	Bandhan Bank	8874096928	CH.LUCKNOW@BANDHANBANK.COM	Khyati

Sr. No.	Name of the Participant	Designation	Bank/Deptt.	Telephone/ Mobile No.	Email Address	Signature
59.	ATHAR ALI	CLUSTER HEAD	YES BANK	9897464983	athar.ali@yesbank.in	
60.	Sumit Tewari	Sr. Manager	NAINITAL BANK	9936285361	nlplucknow@nainitalbank.co.in	
61.	Sandeep Bawa	Regional Head	ICICI Bank	9936306863	sandeep.bawa@icicibank.com	
62.	Ajay Kr. Gupta	Zonal Head	HDFC BANK	9336757823	AJAY KUMAR.GUPTA@HDFCBANK.IN.	
63.	Kumar Gaurav	officer	Punjab and Sind Bank	8789120779.	Kumar.gaurav2@psb.bank.in	
64.	Ankur Khandelwal	Sr. Manager	India Post Payments Bank	7905130059	uttarpradeshcircle@ippbonline.in	
65.	Amit Suyash	Sr Manager	Fino Payments Bank	6391486257	AMIT.SUYASH@FINO.BANK.IN	
66.	Anant Kumar	Dy GM	U.P. coop. Bank Ltd	9919088722	upcb.acd@gmail.com	
67.	DK Prasad	DGM	U.P. State Coop Bank	9415519922	upcbidd@upscb.com	
68.	Aishawary Gupta	Manager	Indian Overseas Bank	9795443845	0814pcdagri@iob.in	
69.	Puneet Shukla	Manager	Central Bank of India	7007981783	zdluckzo@centralbank.bank.in	
70.	Devesh Pratap Singh	Sr. Manager	Canara Bank	9455504252	msmecolwck@canarabank.com	
71.	ANKKIT GUPTA	Sr. Manager	INDIAN BANK	7985180873	FGMO.LUCKNOW@INDIANBANK.BANK.IN	
72.	Sanjeev Kr Singh	Sr. Manager	Bank of India	7017654085	fgmo.lucknow@bankofindia.co.in	
73.	Praveen Yadav	Sr. Manager	Bank of Maharashtra	7355621268	cre_agri_luc@mahabank.co.in	
74.	Ajay Kumar	A-G.M.	State Bank of India	9452183363	agmfi.lholuc@sbi.co.in	
75.	Smriti Tandon	Sr. Manager	Axis Bank Ltd.	9453033224	smriti.tandon@axisbank.com	
76.	Kanchan Srivastava	Chief Manager	ICICI Bank Ltd	8005980341	kanchan.srivastava@icicibank.com	
77.	Sanjay Singh	Asst. Director	Institutional finance deptt.	9412590329		
78.	Abhishek	Consultant-FI	UPSRLM	9771865393	abhi.kumar.cns@microsave.net	
79.	Ruchi Upadhyay..	V.P	Kotak Mahindra Bank	7060222107	ruchi.upadhyay@kotak.com	
80.						
81.						

Sr. No.	Name of the Participant	Designation	Bank/Deptt.	Telephone/ Mobile No.	Email Address	Signature
82.	DEEPAK AGARWAL	AVP	BANDHAN BANK	9839293359	CH.LUCKNOW@BANDHANBANK.COM	[illegible]
83.	Irshad Ah. Wani	Sr. Manager	J&K Bank	7006000721	clulnck@jkbmail.com	[illegible]
84.	Ankita Srivastava	chief Manager	Union Bank	7069070144	rabcl.fgmdudua@unionbankofindia.bank	[illegible]
85.	Pawan Pant	Vice President	AXIS Bank	9044445845	pawan.pant@axisbank.com	[illegible]
86.	Mayur Verma	Sr. Manager	Indusind Bank Ltd	9695512126	mayur.verma@indusind.com	[illegible]
87.	U.K. Mishra	G.M	U.P.G.B	981881604	advances.HO@barodaupgb.com	[illegible]
88.	Sanjeev Tomar	Chief Manager	UPGB	8109217357	"	[illegible]
89.	Snigdha Kiran	Manager	SIDBI	8763934816	snigdhak@sidbi.in	SKiran
90.	Abhishek Singh	Manager	RBI	9319312315	singhabhishek1@rbi.org.in	[illegible]
91.	Abhishek Sinha	D.V.P.	RBL Bank Ltd	9628355551	abhishek.sinha3@RBLBank.in	[illegible]
92.						
93.						
94.						
95.						
96.						
97.						
98.						
99.						
100.						
101.						
102.						
103.						
104.						
105.						